शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
राष्ट्रीय छात्रशक्ति

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष-46 ■ अंक-06 ■ अक्टूबर 2024 ■ ₹10 ■ पृष्ठ-32

नतमस्तक हो फिर जग मांगे
तेरा आशीष भारत मां

ग्रेटर नोएडा : जनजातीय कार्य बैठक का शुभारंभ करते अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य डा. आशुतोष मंडावी, जनजातीय कार्य प्रमुख प्रमोद राउत एवं ओड़िशा प्रांत छात्रा प्रमुख कविता कैंहर

गोरखपुर : 70 वें राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रतीक चिह्न (लोगो) का विमोचन करते अभाविप राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजशरण शाही, संगठन मंत्री आशीष चौहान, अ. भा. छात्रा प्रमुख मनु शर्मा कटारिया, कार्यालय मंत्री दिगंबर पवार, सह कार्यालय मंत्री सौरभ पांडेय एवं अन्य

आवरण चित्र : प्रख्यात कलाकार अवनीद्र नाथ ठाकुर द्वारा उकेरा गया भारत माता का चित्र।

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष-46, अंक-06
अक्टूबर 2024

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक-मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092 से मुद्रित। **संपादक** *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

अबकी बार

08 **संस्कृतिजन्य जीवन दर्शन से सशक्त बनेगा भारत**

पनी स्थापना के 99 वर्ष पूर्ण कर चुके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने देशवासियों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा है कि...

संपादकीय	04
राष्ट्रपति एवं गृहमंत्री से मिले नक्सली हिंसा के पीड़ित	05
जनजातीय समाज के लिए बाबा कार्तिक उरांव ने किया जीवन भर संघर्ष	14
जनजातीय समाज से जुड़े मुद्दों पर अभाविप की बैठक	16
भारतीय एवं पारंपरिक खेलों से होगा राष्ट्र भावना का निर्माण	17
कृत्रिम बुद्धिमत्ता : चुनौतियों के बाद भी दिखती हैं असीम संभावनाएं	18
J&K Assembly Elections : The Aftermath	20
अभाविप ने किया प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित	21
अभाविप ने लहराया जीत का परचम	22
ABVP Shillong Organised Prestigious U. Tirot Sing Best Students Awards	24
ABVP Delegation Met Union Health Minister	25
प्रा. रविंद्र केसरी शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन	26
सोरेन सरकार की विफलताओं पर अभाविप ने जारी किया काला दस्तावेज	27
मिशन साहसी प्रशिक्षण शिविर में छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुर	28
विद्यार्थी पढ़ेंगे 'राष्ट्रीय युद्ध स्मारक' पर कविता	29
एक देश-एक चुनाव	30

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

हाल ही में हरियाणा राज्य एवं जम्मू-कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के चुनाव सम्पन्न हुए। अगले माह झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों में चुनाव होने हैं। देश में लगातार चुनावों का सिलसिला चलता रहता है। अनेक गैर सरकारी संगठनों और बुद्धिजीवियों के सुझाव के बाद केंद्र सरकार ने देश में एक साथ लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव कराने को लेकर आम जनता से राय ली और सार्वजनिक सहमति बनाने का प्रयास किया। इस सम्बंध में सरकार सदन में एक विधेयक भी लेकर आई, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण प्रस्ताव पर गतिरोध बना हुआ है।

यह उल्लेख इसलिए क्योंकि वर्तमान में किसी भी स्तर के चुनाव का अर्थ भारी अराजकता, अनर्गल आरोपों और हिंसक घटनाओं के घटने से लिया जाने लगा है। पहले का वाद-प्रतिवाद अब घात-प्रतिघात का रूप ले चुका है। हारने वाले दल अब विनम्रता से हार स्वीकार करने और आदर्श प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के स्थान पर प्रतिशोध की तैयारी में जुट जाते हैं। विजयी दल से भी और उन नागरिकों से भी, जिन पर उसे वोट न देने का शक हो। ऐसी परिस्थिति में किसी भी क्षेत्र में किसी भी कारण से या अकारण उत्पन्न होने वाला तनाव, हिंसा और अराजकता विपक्ष के लोगों को चिंतित नहीं करता।

जम्मू-कश्मीर में लगातार पांच वर्षों की शांति के बाद एक बार पुनः हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। जिन मार्गों से विगत एक-डेढ़ दशक में घुसपैठ की एक भी घटना दर्ज नहीं हुई थी, वहां से भी घुसपैठ की खबरें आने लगी हैं। करगिल और द्रास में तो करगिल युद्ध के बाद ही इस पर विराम लग गया था, लेकिन वहां से भी घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। इसी तरह गुरेज घाटी भी घुसपैठियों का नया प्रवेश मार्ग बनी है।

जब तक पाकिस्तान सीमा पर है और विश्व की अनेक प्रमुख शक्तियों का समर्थन उसे हासिल है, इस पर नियंत्रण निश्चय ही एक चुनौती है।

जब तक पाकिस्तान सीमा पर है और विश्व की अनेक प्रमुख शक्तियों का समर्थन उसे हासिल है, इस पर नियंत्रण निश्चय ही एक चुनौती है। किन्तु ऐसा लगता है कि विपक्ष इसे देश के विरुद्ध चुनौती न मान कर सत्तारूढ़ भाजपा के लिए चुनौती मान कर चल रहा है। ऐसी बर्बरतापूर्ण घटनाओं पर आतंकियों और उसके पीछे से कठपुतली आतंकी संगठनों का सूत्र संचालन करने वाले पाकिस्तान के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा के लिए प्रशासन एवं सत्ता को समर्थन देने के स्थान पर विपक्षी दल इन घटनाओं के लिये केंद्र सरकार को कठघरे में खड़े करते नजर आते हैं। दुर्भाग्य से इस उलटबांसी का नेतृत्व वही लोग कर रहे हैं, जिन्हें इसी आतंकवाद के चलते अपने परिवार के सदस्यों को खोना पड़ा है।

तथाकथित मानवाधिकारवादियों और गैर-सरकारी संगठनों की एक नई खेप भी अब मैदान में है, जिनके तार उन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से जुड़ते प्रतीत होते हैं जो भारत को अस्थिर करने और उसके विकास में रोड़े अटकाने के षड्यंत्र रच रही हैं। इनके पास विदेशों से आने वाले धन के प्रवाह पर एक सीमा तक तो लगाम लगी है, किन्तु वह पूरी तरह रुका नहीं है।

इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच सम्पन्न होने जा रहे अभाविप के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश की सद्य स्थिति के विषय में चिंतन होगा और इनके प्रतिकार के लिए पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर सहित अन्य ऐसे व्यक्तित्वों के जीवन और कृतित्व को सामने रख कर रचनात्मक रूप से राष्ट्रीय एकात्मता के प्रयासों को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

प्रकाशपर्व दीपावली की हार्दिक मंगलकामनाओं सहित

आपका
संपादक

फोटो : राष्ट्रपति भवन

राष्ट्रपति एवं गृहमंत्री से मिले नक्सली हिंसा के पीड़ित

केंद्र सरकार से बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के सफाए और अपनी समस्याओं का समाधान करने की मांग

दशकों से बस्तर क्षेत्र में जारी नक्सली हिंसा एवं अराजकता के कारण शारीरिक दिव्यांगता का शिकार हुए पीड़ितों ने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके उन्हें अपनी जटिल स्थितियों से अवगत कराया। मुलाकात के दौरान पीड़ितों ने पूरे बस्तर क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त कराने के साथ ही केंद्र सरकार से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाने की मांग की है।

नक्सली हिंसा से पीड़ित बस्तरवासियों के दल ने 'बस्तर शांति समिति' के नेतृत्व में राजधानी दिल्ली में गत 20 एवं 21 सितंबर को कई कार्यक्रमों के माध्यम से अपने अंतहीन दर्द एवं समस्याओं को सामने रखा। 'केंजा नक्सली-मनवा माटा' (सुनो नक्सली - हमारी बात) अभियान के अंतर्गत दिल्ली आए पीड़ितों ने अपनी असहनीय पीड़ा को साझा करते हुए बताया कि बस्तर क्षेत्र में हजारों ग्रामीण लाल आतंकियों के कारण भय के साए में रहने के लिए दशकों से विवश हैं। गत ढाई दशक के दौरान नक्सलियों ने आठ हजार से अधिक ग्रामीणों की हत्या कर दी और नक्सलियों द्वारा बिछाए गए बारूद के ढेर की चपेट में आकर हजारों लोग दिव्यांग हो गए। बस्तर में विकास की बहुत संभावना है,

फोटो : गृह मंत्रालय

लेकिन विकास के रास्ते में नक्सली हिंसा सबसे बड़ी बाधा है। जब भी बस्तर क्षेत्र में कोई नागरिक विकास के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, तब नक्सलियों द्वारा लगाए बम फटकर उसे पुनः उसी आतंक के साए में ले जाते हैं। बस्तरवासी सिर्फ इतना चाहते हैं कि देश उनके दुःख, दर्द और पीड़ा को समझे और उसका भी समाधान निकाले।

राजधानी दिल्ली आए बस्तरवासियों ने अपनी पीड़ा और समस्याओं से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी अवगत कराया। गत 21 सितंबर को राष्ट्रपति मुर्मू से हुई मुलाकात में पीड़ितों ने राष्ट्रपति को बताया कि बस्तर

क्षेत्र सदियों से शांत एवं सुंदर रहा है। लेकिन पिछले चार दशक से नक्सलियों ने बस्तर के शांत क्षेत्र की शांति को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिससे स्थानीय लोग आतंक और भय में जीने के लिए बाध्य हैं। नक्सलियों ने ग्रामीण एवं वन्य क्षेत्रों में बारूदी सुरंग बिछा रखी है, जिसकी चपेट में आकर बस्तरवासी ना सिर्फ गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, बल्कि मारे भी जा रहे हैं। पीड़ितों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर मांग की है कि उनसे जुड़े हुए गंभीर मुद्दों का संज्ञान लेकर पूरे बस्तर क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त कराया जाए।

अपनी जटिल स्थितियों से अवगत कराने के लिए सभी पीड़ितों ने गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाक़ात की। पीड़ितों से हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए उग्रवादियों के मानवाधिकारों की बात करने वाले लोगों को बिना आंख, बिना हाथ, बिना पैर के जीवन जीने के लिए मजबूर लोगों के मानवाधिकार नजर नहीं आते। उन्होंने पीड़ितों को आश्वासन देते हुए कहा कि मोदी सरकार आगामी दो वर्ष के अन्दर नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करके बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए संकल्पित है।

लाल आतंक से पीड़ित पहुंचे जेएनयू

नक्सली हिंसा के कारण दिव्यांग हुए पीड़ितों के समूह ने राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू में पहुंच कर अपने दर्द को साझा किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने गत 20 सितंबर को विश्वविद्यालय के साबरमती ढाबे पर नक्सलवाद के विरोध में एक चर्चा का आयोजन किया। चर्चा के दौरान पीड़ित मंगऊ राम कावड़े ने बताया कि वह जेनएयू आकर बस्तर की वास्तविक स्थिति को सामने रखना चाहते थे। जेएनयू में नक्सलवाद-माओवाद के समर्थन में बड़े-बड़े कार्यक्रम होते हैं। यहां कथित बुद्धिजीवी नक्सलियों के मानवाधिकार की बात करते हैं। लेकिन वह कभी भी नक्सल पीड़ितों की चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए वह जेनएयू परिसर में अपनी पीड़ा को बताने के लिए आए हैं।

जेएनयू में चर्चा कार्यक्रम के दौरान 'आमचो बस्तर' के लेखक राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि उनके लिए यह क्षण भावुक और आक्रोशित, दोनों करने वाला है। दिल्ली और जेएनयू की धरती पर अर्बन नक्सलियों और माओवादियों की बातें तो कई बार की गई, लेकिन वास्तविक नक्सल पीड़ितों की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचने में चार दशक लग गए। बस्तर की समस्या का समाधान वामपंथी प्रदर्शन और माओवादी आतंक से नहीं हो सकता है। एक अन्य पीड़ित केदारनाथ कश्यप ने बताया कि किस तरह नक्सलियों ने उनके सामने ही उनके भाई की निर्ममता से हत्या कर दी थी। एक अन्य पीड़ित सियाराम रामटेके, जो नक्सलियों की गोली के कारण कमर से नीचे पूरी तरह से दिव्यांग हो चुके हैं, ने भी अपनी व्यथा को सभी के सामने रखा। कमोवेश सभी पीड़ितों की कहानी लगभग एक जैसी ही है। नक्सली हिंसा के कारण किसी ने अपने पैर को खो दिया तो किसी की आंखें चली गई। किसी के कान में चोट है, तो कोई चल नहीं सकता है।

बस्तर शांति समिति के सदस्य जयराम दास ने बताया कि नक्सल हिंसा से पीड़ित बस्तर के लोग जेनएयू के उन बुद्धिजीवियों को आईना दिखाने के लिए आए हैं, जिन्हें नक्सलवाद 'क्रांति' लगता है। अभाविप जेएनयू इकाई के अध्यक्ष राजेश्वर कांत दुबे के अनुसार अभाविप हमेशा से नक्सलवाद मुक्त समृद्ध भारत बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। परंतु जेएनयू में कुछ लोग वामपंथी विचारधारा का आम छात्रों के बीच गुणगान करते हैं। ऐसे में छात्रों को सच्चाई से अवगत कराना अभाविप का कर्तव्य है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

संस्कृतिजन्य जीवन दर्शन से सशक्त बनेगा भारत

अपनी स्थापना के 99 वर्ष पूर्ण कर चुके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने देशवासियों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा है कि भारत का राष्ट्र जीवन सांस्कृतिक एकात्मता एवं श्रेष्ठ सभ्यता की सुदृढ़ आधारशिला पर खड़ा है। ऐसे राष्ट्र जीवन को क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के कु-प्रयासों को समय पूर्व रोकना आवश्यक है। इसके लिए भारत के संस्कृतिजन्य जीवन दर्शन तथा संविधान प्रदत्त मार्ग से लोकतंत्रीय मार्ग को अपनाकर एक सशक्त विमर्श खड़ा करना होगा क्योंकि वैचारिक एवं सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने वाले इन षड्यंत्रों से समाज को सुरक्षित रखना समय की आवश्यकता है।

विजयादशमी पर्व के अवसर पर गत 12 अक्टूबर को नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर हर्ष व्यक्त करते हुए सरसंघचालक डा. भागवत ने कहा कि गत वर्षों में भारत

एक राष्ट्र के तौर पर विश्व में सशक्त और प्रतिष्ठित हुआ है। विश्व में उसकी साख बढ़ी है। कई क्षेत्रों में भारतीय परम्परा तथा भावना में अन्तर्निहित विचारों का सम्मान बढ़ा है। विश्वबंधुत्व की भावना,पर्यावरण के प्रति हमारी दृष्टि की स्वीकृति, योग इत्यादि को विश्व निःसंकोच स्वीकार कर रहा है। इससे समाज में विशेषकर युवा पीढ़ी में "स्व" का गौरव बोध बढ़ता जा रहा है। विश्वास है कि देश की युवा शक्ति, मातृशक्ति, उद्यमी, किसान, श्रमिक, जवान, प्रशासन, शासन सभी, प्रतिबद्धतापूर्वक अपने-अपने कार्य में डटे रहेंगे।

भारत को अस्थिर करने की कोशिश

विश्व में सशक्त और प्रतिष्ठित हो रहे भारत को अस्थिर करने के प्रयासों पर चिंता प्रकट करते हुए सरसंघचालक डा. भागवत ने कहा कि गत वर्षों में देशहित की प्रेरणा से किए गए पुरुषार्थ से ही विश्वपटल पर भारत की छवि, शक्ति, कीर्ति एवं स्थान निरन्तर उन्नत हो रहा है। इसके साथ ही देश के चारों तरफ के क्षेत्रों को अशांत एवं अस्थिर करने के प्रयास भी गति पकड़ते हुए दिखाई देते हैं।

विश्व में भारत के बढ़ते कदम के बीच कई शक्तियां भारत को रोकने का प्रयास कर रही हैं। स्वयं को उदार एवं जनतांत्रिक स्वभाव का बताते हुए विश्वशांति के लिए कटिबद्ध दिखाई देने वाले देश, अन्य देशों पर आक्रमण करने में अथवा जनतांत्रिक पद्धति से चुनी गई वहां की सरकारों को अवैध अथवा हिंसक तरीकों से गिराने में चूकते नहीं हैं। ऐसे में भारत की छवि को मलिन करने के लिए किए जा रहे प्रयास, असत्य अथवा अर्धसत्य के आधार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

बांग्लादेश की चिंताजनक स्थिति

बांग्लादेश में हिंसक तरीके से हुए सत्ता परिवर्तन की चर्चा करते हुए सरसंघचालक डा. भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ, उसके तात्कालिक एवं स्थानीय कारण उस घटनाक्रम का एक पहलू हैं। लेकिन वहां रहने वाले हिन्दू समाज पर पुनः अकारण नृशंस अत्याचार किए गए। इसके विरोध में हिन्दू समाज संगठित होकर स्वयं के बचाव में घर से बाहर आया। इसलिए थोड़ा बचाव हुआ। परन्तु यह अत्याचारी कट्टरपंथी स्वभाव जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां रहने वाले हिन्दुओं सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के सिर पर खतरे की तलवार लटकी रहेगी। बांग्लादेश से भारत में होने वाली अवैध घुसपैठ एवं उसके कारण उत्पन्न जनसंख्या असंतुलन भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अवैध घुसपैठ के कारण देश में आपसी सद्भाव एवं सुरक्षा पर भी प्रश्न चिह्न लगते हैं। ऐसे में उदारता, मानवता तथा सद्भावना के पक्षधर लोगों को बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिन्दू समाज की सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से मिलाने का विमर्श खड़ा किया जा रहा है। ऐसे विमर्श खड़ा करके कौन से देश भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं? चिन्ता की बात यह है कि समाज में विद्यमान भद्रता एवं संस्कार को नष्ट-भ्रष्ट करने, विविधता को अलगाव में बदलने, समस्याओं से पीड़ित समूहों में व्यवस्था के प्रति अविश्वास करने तथा असन्तोष को अराजकता में रूपांतरित करने के प्रयास बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में समझना होगा कि असंगठित एवं दुर्बल

होना दुष्टों के अत्याचारों को निमंत्रण देता है और यह पाठ वैश्विक हिन्दू समाज को ग्रहण करना ही होगा।

सांस्कृतिक परम्पराओं को नष्ट करने का प्रयास

'डीप स्टेट', 'वोकिज्म ', 'कल्चरल मार्क्सिस्ट' जैसे शब्दों की चर्चा करते हुए सरसंघचालक डा. भागवत ने कहा कि वास्तव में यह सभी सांस्कृतिक परम्पराओं के घोषित शत्रु हैं। सांस्कृतिक मूल्यों, परम्पराओं तथा जो भी भद्र एवं मंगल माना जाता है, उसका समूल उच्छेद इस समूह की कार्यप्रणाली का अंग है। समाज को प्रभावित करने वाले तंत्र एवं संस्थानों को अपने प्रभाव में लाना, उनके द्वारा समाज का विचार, संस्कार तथा आस्था को नष्ट करना, इस कार्यप्रणाली का प्रथम चरण होता है। एक-साथ रहने वाले समाज में किसी घटक को उसकी कोई वास्तविक या कृत्रिम रीति से उत्पन्न की गई विशिष्टता, मांग, आवश्यकता अथवा समस्या के आधार पर अलगाव के लिए प्रेरित किया जाता है। उनमें अन्यायग्रस्तता की भावना उत्पन्न की जाती है और असंतोष को हवा देकर उस घटक को शेष समाज से अलग करके व्यवस्था के विरुद्ध उग्र बनाया जाता है। समाज में प्रत्यक्ष टकराव खड़े किए जाते हैं। व्यवस्था, कानून, शासन, प्रशासन आदि के प्रति अविश्वास एवं द्वेष को उग्र बना कर अराजकता एवं भय का वातावरण बनाया जाता है, जिससे किसी देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करना सरल हो जाता है।

राजनीतिक दलों की नकारात्मक स्पर्धा

बहुदलीय प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों की नकारात्मक स्पर्धा पर टिप्पणी करते हुए सरसंघचालक डा. भागवत ने कहा कि समाज में विद्यमान छोटे स्वार्थ, परस्पर सद्भावना अथवा राष्ट्र की एकता-अखंडता से अधिक महत्वपूर्ण होने अथवा दलों की स्पर्धा में समाज की सद्भावना एवं राष्ट्र गौरव और एकात्मता के गौण होने की स्थिति में भारत विरोधी शक्तियां, ऐसी दलीय राजनीति में एक पक्ष की सहायता में खड़ी होकर पर्यायी राजनीति के नाम पर, अपनी विघटनकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कार्यपद्धति को अपनाती हैं। यह विश्व के अनेक देशों पर बीती हुई वास्तविकता है। पाश्चात्य जगत के कई देश इस मंत्रविप्लव के परिणामस्वरूप जीवन की स्थिरता, शांति एवं मांगल्य संकट में पड़े हुए प्रत्यक्ष दिखाई देते है। तथाकथित "अरब स्प्रिंग" से लेकर बांग्लादेश में इस कार्यपद्धति को काम करते हुए देखा जा चुका है और भारत के चारों ओर विशेषकर सीमावर्ती तथा जनजातीय जनसंख्या वाले प्रदेशों में हो रहे कुप्रयासों को देखा जा सकता है।

संस्कार क्षरण के दुष्परिणाम

विभिन्न तंत्रों तथा संस्थानों के विकृत प्रचार एवं कु-संस्कार से प्रभावित हो रही देश की नई पीढ़ी के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए सरसंघचालक डा. भागवत ने कहा कि बड़ों के साथ-साथ अब बच्चों के हाथों में भी मोबाइल पहुंच गया है। बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह काफी वीभत्स है। समाज में विज्ञापनों तथा विकृत दृश्य-श्रव्य सामग्री पर कानून के कठोर नियंत्रण की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी में नशीले पदार्थों की आदत भी समाज को अंदर से खोखला कर रही है। ऐसे में सभी को अच्छाई की ओर ले जाने वाले संस्कार पुनर्जीवित करने होंगे।

उन्होंने कहा कि संस्कार क्षय का ही यह परिणाम है कि "मातृवत् परदारेषु" के आचरण की मान्यता वाले देश में बलात्कार जैसी घटनाओं का मातृशक्ति को कई जगह सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता के आर.जी. कर अस्पताल में घटी घटना समाज को कलंकित करने वाली लज्जाजनक घटनाओं में एक है। उसके निषेध तथा त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई की मांग को लेकर चिकित्सक बंधुओं के साथ सारा समाज तो खड़ा हुआ। परन्तु ऐसा जघन्य पाप होने पर भी कुछ लोगों द्वारा जिस प्रकार अपराधियों को संरक्षण देने के घृणास्पद प्रयास किए गए, यह सब अपराध, राजनीति तथा अपसंस्कृति के गठबंधन को दिखाता है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति "मातृवत् परदारेषु" की दृष्टि भारतीय सांस्कृतिक देन है जो हमें अपनी संस्कार परम्परा से प्राप्त होती है। परिवार तथा समाज, जिनसे मनोरंजन के साथ ही जाने-अनजाने प्रबोधन भी प्राप्त कर रहा है, उन माध्यमों में इस सम्बन्ध में ध्यान नहीं दिया जाना, इन मूल्यों की उपेक्षा या तिरस्कार का होना, बहुत महंगा पड़ रहा है। इसलिए परिवार, समाज तथा संवाद माध्यमों द्वारा सांस्कृतिक मूल्यों के प्रबोधन की व्यवस्था को फिर से जागृत करना ही होगा।

संस्कार जागरण

संस्कारों के क्षरण को रोकने के लिए संस्कार प्रदान करने की

भारतीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित, समर्थ एवं सक्षम बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सरसंघचालक डा. भागवत ने कहा कि शिक्षा पद्धति आजीविका की शिक्षा देने के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास का भी काम करती है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्य सारांश में बताने वाला एक सुभाषित है-

मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्।
आत्मवत् सर्व भूतेषु यः पश्यति सः पंडितः।।

इसलिए महिलाओं को माता समान देखने की दृष्टि, पराया धन मिट्टी समान मानते हुए स्वयं के परिश्रम से एवं सन्मार्ग से ही धनार्जन करना और दूसरों को दुःख कष्ट हो, ऐसा आचरण या कार्य नहीं करना, जैसे व्यवहार करने वाले को शिक्षित माना जाता है। नई शिक्षा नीति में ऐसी मूल्य शिक्षा की व्यवस्था एवं तदनुरूप पाठ्यक्रम का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों के उदाहरण छात्रों के सामने उपस्थित हुए बिना यह शिक्षा प्रभावी नहीं होगी। इसलिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की नई व्यवस्था करनी होगी। साथ ही समाज के वह प्रमुख लोग, जिनकी लोकप्रियता के कारण अनेक लोग उनका अनुकरण करते हैं, उनके आचरण में यह दिखना चाहिए। समाज में चलने वाले विभिन्न प्रबोधन कार्यों से यह मूल्य प्रबोधन किया जाना चाहिए। घर में बड़ों का व्यवहार, वातावरण और आत्मीयता युक्त संवाद से यह शिक्षा संपन्न होती है। शिक्षा का मूलारम्भ एवं उसके कारण बनने वाली स्वभाव प्रवृत्ति तीन से बारह वर्ष की आयु में घर में ही बनती है। स्व गौरव, देश प्रेम, नीतिमत्ता, श्रेयबोध, कर्तव्यबोध आदि कई गुणों का निर्माण इसी कालावधि में होता है। यह समझकर सभी को यह कार्य स्वयं अपने घर से प्रारम्भ करना पड़ेगा।

शक्ति का महत्व

सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने कहा कि आज भारत में सामान्य समाज को जाति, भाषा, प्रान्त आदि छोटी विशेषताओं के आधार पर अलग करके टकराव उत्पन्न करने का प्रयास जारी है। छोटे स्वार्थ एवं छोटी पहचानों में उलझकर सर पर मंडराते बड़े संकट को समाज समझ न सके, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। सीमा से लगे पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, केरल, तमिलनाडु तथा बिहार से मणिपुर तक का सम्पूर्ण पूर्वांचल अस्वस्थ है। देश में कट्टरपन को उकसाने वाली घटनाओं में भी अचानक वृद्धि दिखाई दे रही है। परिस्थिति या नीतियों को लेकर असंतुष्टि होने पर उनका विरोध करने के लिए प्रजातांत्रिक मार्ग के स्थान पर हिंसा पर उतर आना, समाज के एकाध विशिष्ट वर्ग पर आक्रमण करना, हिंसा पर उतारू होना, भय पैदा करने का प्रयास करना या उकसाने के प्रयास योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। ऐसे ही आचरण को बाबासाहब डा. भीम राव आंबेडकर ने अराजकता का व्याकरण (Grammar of Anarchy) कहा है। गणेशोत्सवों के समय श्रीगणपति विसर्जन की शोभायात्राओं पर पथराव तथा उसके बाद बनी तनावपूर्ण परिस्थिति की घटनाएं इसी व्याकरण का उदाहरण हैं। इसलिए समाज को अपने तथा अपनों के प्राणों एवं सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए सदैव सतर्क रहने तथा इन कुप्रवृत्तियों को और उन्हें प्रश्रय देने वालों को पहचानने की आवश्यकता है।

व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय चारित्र्य

निःस्वार्थ भावना से देश, धर्म, संस्कृति एवं समाज के हित में जीवन लगा देने वाली विभूतियों को स्मरण करते हुए सरसंघचालक डा. भागवत ने कहा कि ऐसी विभूतियों ने सबके हित में कार्य तो किया ही, अपितु अपने स्वयं के जीवन से अनुकरणीय जीवन व्यवहार का उत्तम उदाहरण सामने रखा। निस्पृहता, निर्वैरता एवं निर्भयता उनका स्वभाव था। संघर्ष का कर्तव्य जब-जब उपस्थित हुआ, तब-तब पूर्ण शक्ति के साथ, आवश्यक कठोरता बरतते हुए उन्होंने उसे निभाया। उज्ज्वल शीलसंपन्नता उनके जीवन की पहचान थी। इसलिए उनकी उपस्थिति दुर्जनों के लिए धाक एवं सज्जनों को आश्वस्त करने वाली थी। आज इसी प्रकार के जीवन व्यवहार की अपेक्षा परिस्थिति कर रही है। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय चारित्र्य की ऐसी दृढ़ता ही मांगल्य व सज्जनता की विजय के लिए शक्ति का आधार बनती है।

संस्कार एवं सामाजिक व्यवहार

सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने कहा कि संस्कारों की अभिव्यक्ति का दूसरा पहलू सामाजिक व्यवहार है। समाज में एक साथ और सुखपूर्वक रहने के लिए कुछ नियम बने होते हैं। देश काल परिस्थितिनुसार नियमों में परिवर्तन भी होता रहता है। इन नियमों के श्रद्धापूर्वक पालन की अनिवार्यता रहती है। एकजुट रहने की स्थिति में परस्पर व्यवहार के प्रति भी कुछ कर्तव्य और अनुशासन बन जाते हैं। कानून एवं संविधान ऐसा ही एक सामाजिक अनुशासन है। संविधान

की प्रस्तावना इस भाव को ध्यान में रखकर संविधान प्रदत्त कर्तव्यों और कानून का योग्य निर्वहन सभी को करना होता है। नियम एवं व्यवस्था का पालन ठीक प्रकार से हो सके, इसके लिए संविधान की प्रस्तावना, मार्गदर्शक तत्व, नागरिक कर्तव्य एवं नागरिक अधिकार का प्रबोधन सर्वत्र होते रहना चाहिए। परिवार से प्राप्त पारस्परिक व्यवहार का अनुशासन, परस्पर व्यवहार में मांगल्य, सद्भावना और भद्रता तथा सामाजिक व्यवहार में देशभक्ति एवं समाज के प्रति आत्मीयता के साथ कानून-संविधान का निर्दोष पालन से व्यक्ति का व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय चारित्र्य बनता है। देश की सुरक्षा, एकात्मता, अखण्डता एवं विकास के लिए चारित्र्य के इन पहलुओं का त्रुटिविहीन एवं सम्पूर्ण होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मन, वचन एवं कर्म का विवेक

विविधता में एकता की चर्चा करते हुए सरसंघचालक डा. भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय चारित्र्य के व्यवहार का एक और महत्वपूर्ण पहलू किसी भी प्रकार की अतिवादिता तथा अवैध पद्धति से स्वयं को दूर रखना है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। विविधताएं सृष्टि की स्वाभाविक विशिष्टताएं है। प्राचीन इतिहास, विस्तीर्ण क्षेत्रफल तथा विशाल जनसंख्या वाले देश में यह सभी विशिष्टताएं स्वाभाविक हैं। अपनी-अपनी विशिष्टता का गौरव तथा उनके प्रति अपनी-अपनी संवेदनशीलता भी स्वाभाविक है। इस विविधता के चलते समाज जीवन में एवं देश के संचालन में होने वाले सभी कार्य सदा-सर्वदा सबके अनुकूल अथवा सबको प्रसन्न करने वाली होंगे, ऐसा नहीं होता। इनकी प्रतिक्रिया में कानून-व्यवस्था को किनारे रखकर अवैध या हिंसात्मक मार्ग से उपद्रव खड़ा करना, समाज के किसी एक सम्पूर्ण वर्ग को इसका जिम्मेदार मानना, मन-वचन और कर्म से मर्यादा का उल्लंघन करना, देश और देश की जनता के लिए न विहित है और न हितकारी है। जिस प्रकार कुटुंब में समर्थ घटक दुर्बल घटकों के लिए अधिक प्रावधान, कभी-कभी अपना नुकसान सहन करके भी करते हैं, वैसे अपनेपन की दृष्टि रखकर ऐसी आवश्यकताओं का विचार होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि समाज में अनेक जाति वर्गों का संचालन करने वाली उनकी अपनी-अपनी रचनाएं एवं संस्थाएं भी हैं। अपने-अपने जाति वर्ग की उन्नति, सुधार तथा उनके हित प्रबोधन का विचार इन रचनाओं के नेतृत्व के द्वारा किया जाता है। जाति बिरादरी के नेतृत्व करने वाले लोग मिल बैठकर विचार करेंगे तो समाज में सर्वत्र सद्भावनापूर्ण व्यवहार का वातावरण बनेगा। समाज को बांटने का कोई कुचक्र सफल हो नहीं सकेगा।

पर्यावरण अनुकूल विकास

पर्यावरण की दुःस्थिति पर दुःख व्यक्त करते हुए सरसंघचालक डा. भागवत ने कहा कि यह एक विश्वव्यापी समस्या है। ऋतुचक्र अनियमित एवं उग्र बन गया है। उपभोगवादी तथा जड़वादी अधूरे वैचारिक आधार पर चली मानव की तथाकथित विकास यात्रा मानवों सहित सम्पूर्ण सृष्टि की विनाश यात्रा बन गई है। भारतवर्ष की परम्परा से प्राप्त सम्पूर्ण, समग्र एवं एकात्म दृष्टि के आधार पर विकास पथ को बनाना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। विकास के बहाने विनाश की ओर ले जाने वाले अधूरे विकास पथ के अन्धानुसरण के परिणाम सभी भोग रहे हैं। जंगल काटने से हरियाली नष्ट हो गई, नदियां सूख गईं, रसायनों ने अन्न, जल, वायु एवं धरती तक को विषाक्त कर दिया, पर्वत ढह रहे हैं और भूमि फटने लगी है। यह सारे अनुभव पिछले कुछ वर्षों में देश अनुभव कर रहा है। अपने वैचारिक आधार पर, इस नुकसान को पूरा कर धारणाक्षम, समग्र एवं एकात्म विकास देने वाले पथ का निर्माण करें, इसका कोई पर्याय नहीं है। सम्पूर्ण देश में इसकी समान वैचारिक भूमिका बने एवं देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वयन का विकेन्द्रित विचार हो, यह तब ही होगा। पर्यावरण के सम्बन्ध में नीतिगत प्रश्नों का समाधान के लिए त्वरित प्रयास करने होंगे।

शक्ति युक्त शील ही उन्नति का आधार

सरसंघचालक डा. भागवत ने कहा कि सत्य को अपने मूल्य पर जगत स्वीकार नहीं करता, बल्कि जगत शक्ति को स्वीकार करता है। भारत वर्ष बड़ा होने से दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में सद्भावना एवं संतुलन उत्पन्न होकर शान्ति और बंधुता की ओर विश्व बढ़ेगा, यह विश्व में सब राष्ट्र जानते हैं। फिर भी अपने संकुचित स्वार्थ और अहंकार या द्वेष को लेकर शक्तिशाली देशों की भारत को एक मर्यादा में बांधकर रखने की चेष्टा को सब अनुभव करते हैं। भारत वर्ष की शक्ति जितनी बढ़ेगी, उतनी ही भारत वर्ष की स्वीकार्यता रहेगी। बलहीनों को कोई नहीं पूछता, बलवानों को विश्व

पूजता-यह आज के जगत की रीति है। इसलिए सद्भाव एवं संयमपूर्ण वातावरण की स्थापना के लिए शक्ति संपन्न होना ही पड़ेगा। शक्ति जब शीलसंपन्न होकर आती है, तब वह शान्ति का आधार बनाती है। दुर्जन स्वार्थ के लिए एकत्र और सजग रहते हैं। उन पर नियंत्रण सशक्त ही कर सकते हैं। सज्जन सबके प्रति सद्भाव रखते हैं, परन्तु एकत्र होना नहीं जानते। इसीलिए दुर्बल दिखाई देते हैं। उनको यह संगठित सामर्थ्य के निर्माण की कला सीखनी होगी। शील संपन्न व्यवहार के साथ शक्ति की साधना भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में कोई परास्त न कर सके, ऐसी शक्ति और विश्व विनम्र हो, ऐसा शील भगवान से मांगा गया है। विश्व एवं मानवता के कल्याण का कोई काम अनुकूल परिस्थिति में भी इन दो गुणों के बिना संपन्न नहीं होता। यही साधना अपनी पवित्र मातृभूमि को परमवैभव संपन्न बनाने की शक्ति एवं सफलता प्रदान करेगी।

महापुरुषों का अभिनंदन

सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने कहा कि महारानी दुर्गावती की जन्मजयंती का 500वां वर्ष, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर की जन्मजयंती का 300वां वर्ष, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्मजयंती 200वां वर्ष पूरा देश मना रहा है। बिरसा मुंडा की जन्मजयंती का 150वां वर्ष भी आगामी नवंबर माह से आरम्भ होगा। भारत वर्ष के नवोत्थान की यह सभी प्रेरक शक्तियां हैं। रामराज्य सदृश जैसा वातावरण निर्माण करने में प्रजा की गुणवत्ता, चारित्र्य तथा स्वधर्म पर दृढ़ता होना अनिवार्य है। वैसा संस्कार एवं दायित्वबोध उत्पन्न करने वाला "सत्संग" अभियान परमपूज्य अनुकूलचन्द्र ठाकुर के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। वर्तमान बांग्लादेश तथा तत्कालीन उत्तर बंगाल के पाबना में जन्म लेने वाले स्वर्गीय अनुकूलचन्द्र ठाकुर होमियोपैथी चिकित्सक थे। वह अपनी माता द्वारा ही अध्यात्म साधना में दीक्षित थे। व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर उनके सम्पर्क में आने वाले लोगों में सहज रूप से चरित्र विकास तथा सेवा भावना के विकास की प्रक्रिया ही 'सत्संग' बनी, जिसे 1925 में धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया। 2024 से 2025 'सत्संग' के मुख्यालय देवघर (झारखंड) में उस कर्मधारा की भी शताब्दी मनाई जाएगी। विकास के अनेक उपक्रमों को लेकर यह अभियान आगे बढ़ रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मजयंती जनजातीय बंधुओं की गुलामी तथा शोषण, स्वदेश पर विदेशी वर्चस्व से मुक्ति, अस्तित्व एवं अस्मिता की रक्षा एवं स्वधर्म रक्षा के लिए भगवान बिरसा मुंडा द्वारा प्रवर्तित उलगुलान की प्रेरणा का स्मरण कराती है। भगवान बिरसा मुंडा के तेजस्वी जीवनयज्ञ के कारण ही अपने जनजातीय बंधुओं के स्वाभिमान, विकास तथा राष्ट्रीय जीवन में योगदान के लिए एक सुदृढ़ आधार मिल गया है।

भारत के बढ़ते कदम

भारत को एकात्म, सुख शान्तिमय, समृद्ध एवं बल संपन्न बनाने में कर्तव्य की भूमिका को रेखांकित करते हुए सरसंघचालक डा. भागवत ने कहा कि समाज स्वयं जागता है, अपने भाग्य को अपने पुरुषार्थ से लिखता है, तब महापुरुष, संगठन, संस्थाएं, प्रशासन, शासन आदि सहायक होते हैं। इसलिए 'स्व गौरव' की प्रेरणा आवश्यक है। हम कौन हैं? हमारी परम्परा और हमारा गंतव्य क्या है? भारतवासियों को विविधताओं के बावजूद जो बड़ी, सर्व समावेशक, प्राचीन काल से चलती आ रही मानवीय पहचान मिली है, उसका स्पष्ट स्वरूप क्या है? इसका ज्ञान होना आवश्यक है। स्व-गौरव की प्रेरणा का बल ही जगत में उन्नति एवं स्वावलंबन का कारण बनने वाला व्यवहार उत्पन्न करता है। इसको स्वदेशी का आचरण कहते हैं। राष्ट्रीय नीति में उसकी अभिव्यक्ति बहुत बड़ी मात्रा में, समाज में दैनंदिन जीवन में व्यक्तियों द्वारा होने वाले स्वदेशी व्यवहार पर निर्भर करती है। इसी को स्वदेशी का आचरण कहते हैं। अपनी परंपरा का ध्यान रखना ही स्वदेशी व्यवहार है। सब क्षेत्रों में देश के स्वावलंबी बनने से स्वदेशी व्यवहार करना सरल होता है। इसलिए स्वतन्त्र देश की नीति में देश के स्वावलंबी बनने का परिणाम देने वाली नीति जुड़नी चाहिए। साथ ही समाज को स्वदेशी व्यवहार को जीवन तथा स्वभाव का अंग बनाना होगा, तभी भारत के बढ़ते हुए कदमों को गति मिल सकेगी।

जानकारी हो कि दशहरा पर्व पर आयोजित समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष डा. कोपिल्लिल राधाकृष्णन के साथ विदर्भ प्रांत के संघचालक, सह संघचालक, नागपुर महानगर के संघचालक सहित अधिकारी गण, नागरिक, माता भगिनी तथा बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित रहे। ■

(विजयादशमी पर्व के अवसर पर नागपुर में दिए गए उद्बोधन के संपादित अंश)

जनजातीय समाज के लिए बाबा कार्तिक उरांव ने किया जीवन भर संघर्ष

■ अजीत कुमार सिंह

जनजातीय समाज के अधिकारों की लडाई के अग्रदूत बाबा कार्तिक उरांव को समाज का रक्षक कहा जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बाबा उरांव जीवनपर्यंत जनजातीय समाज के हितों की रक्षा एवं संविधान प्रदत्त अधिकारों के लिए संघर्षशील रहे। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात जनजातीय समाज जिस आवाज को ढूंढ रहा था, डा. कार्तिक उरांव न केवल उसकी आवाज बने, बल्कि संपूर्ण समाज के शैक्षणिक-सांस्कृतिक उत्थान के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए अथक प्रयास किए। जनजातीय समाज के साथ हो रहे धोखे को उन्होंने उजागर किया और समाज के हितों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया। उनका मानना था कि मतांतरित हुए जनजातीय लोग, जो अपनी संस्कृति, परंपरा से कटकर विदेशी संस्कृति अपना लेते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

जनजातीय समाज की पीड़ा को समझने वाले झारखंड (तत्कालीन बिहार) के अनमोल रत्न डा. कार्तिक उरांव पहले ऐसे राजनेता थे, जिनके पास अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) की नौ डिग्रियां थीं। बाबा उरांव का जन्म झारखंड के गुमला जिले के लिटाटोली में 29 अक्टूबर 1924 को हुआ था। बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी बाबा उरांव ने अभियांत्रिकी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया। उच्च शिक्षा के लिए वह इंग्लैण्ड गए। अत्यंत सम्पन्न जीवन का भविष्य होते हुए भी उन्होंने समाज की पीड़ा को समझा और सार्वजनिक जीवन में जनजातीय समाज के दुःखों को दूर करने के लिए राजनीति में प्रवेश किया। 1967 में वह लोहरदगा सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। वह केन्द्र सरकार में मंत्री भी रहे। जन प्रतिनिधि के रुप में कार्य करने के दौरान उन्होंने जनजातीय समाज की समस्याओं को

काफी निकट से देखा, समझा और जाना।

चर्च एवं मिशनरी संस्थाओं द्वारा भोले-भाले जनजातीय लोगों का किया जाने वाले मतांतरण ने उन्हें परेशान किया। उन्होंने देखा कि किस प्रकार जनजातीय समाज के मतांतरित लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तथा इससे जनजातीय समाज के लोगों को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। जनजातीय समाज के साथ हो रहे इस अन्याय को लेकर वह दुःखी हुए और फिर संसद में रहते हुए उन्होंने लगातार जनजातियों के हित में प्रखर आवाज उठाई। उन्हीं के प्रयत्नों से संसद द्वारा 1968-69 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया और उसकी अनुशंसाओं के आधार पर संसद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

आदेश (संशोधन) विधेयक-1969 प्रस्तुत किया गया। बाबा उरांव ने अपने अनुभव के आधार पर कहा था कि मतांतरित जनजाति सदस्यों द्वारा सारी संवैधानिक सुविधाएं हड़प लिए जाने के कारण वास्तविक जनजातियों के लिए यह बीस वर्ष की अवधि एक काली रात के समान है। इसी काली रात के अंधेरे से निकलकर जनजातीय समाज को अपने अधिकारों और सुविधाओं को प्राप्त कर नया सवेरा लाना पड़ेगा।

बाबा उरांव ने अपने स्वयं के अध्ययन के अनुसार भारत के जनजातीय समाज की परिस्थिति का चित्रण तीन भागों में किया। पहला भाग भारतीय संविधान के लागू होने के पूर्व का काल अर्थात 1950 के पूर्व का काल। दूसरा भाग संविधान लागू होने के पश्चात अर्थात् 1950 से आज तक का काल और तीसरा भाग जनजातीय समाज के आने वाले कल की परिस्थिति। संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ समाजिक भेदभाव का शिकार होने के कारण आरक्षण की सुविधा प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के विशेष रीति-रिवाज, संस्कृति एवं परंपरा को बचाए रखने के लिए उन्हें भी आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। यदि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई व्यक्ति मतांतरित हो जाता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। इसका प्रावधान संविधान में है। लेकिन कोई अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति यदि मतांतरित हो जाता है तो उसे आरक्षण का लाभ मिलता रहता है। वास्तव में इसे संविधान की विसंगति ही कहा जाएगा।

जनजातीय समाज में सभी रीति-रिवाज, सामाजिक व्यवस्था एवं पारंपरिक उत्सव अपने आराध्य देवी-देवता एवं देव स्थान के प्रति आस्था एवं विश्वास के प्रति आधारित होते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ मतांतरित लोग अपनी संस्कृति, आस्था, परंपरा को त्याग कर ईसाई या मुसलमान हो गए हैं और सुविधाओं का 80 प्रतिशत लाभ मूल जनजाति समाज से छीन रहे हैं। बाबा उरांव ने यह सब भलीभांति अनुभव किया। इससे वह काफी व्यथित हुए। उनका दुःख पूरे भारत के जनजातीय समाज के लिए था। जनजातीय समाज के साथ हो रहे अन्याय का उन्होंने विरोध किया और संविधान की इस भयानक विसंगति को लेकर देश में एक बडी बहस खडी की।

बाबा उरांव ने 10 नवंबर 1970 को 348 संसद सदस्यों (322 लोकसभा और 26 राज्यसभा) के हस्ताक्षरयुक्त एक ज्ञापन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सौंपा, जिसमें संयुक्त संसदीय समिति की संस्तुति को स्वीकार करने की मांग की गई। परंतु इंदिरा सरकार इस विषय के क्रियान्वयन पर बहस कराने का साहस नहीं दिखा पाई। 16 नवंबर 1970 को लोकसभा में बहस शुरू हुई और 17 नवंबर 1970 को केंद्र सरकार की ओर से एक संशोधन पेश किया गया कि विधेयक में से संयुक्त संसदीय समिति की उस संस्तुति को हटा लिया जाए। यह पूरे जनजातीय समाज के हितों पर भयंकर वज्राघात था। इस पर भी बाबा उरांव ने हार नहीं मानी और 24 नवंबर 1970 को लोकसभा में जोरदार बहस करते हुए संयुक्त संसदीय समिति की संस्तुति को मंजूर करने की पुरजोर मांग की।

बहस के दौरान वह इतने भावुक हो गए कि उन्होंने सरकार से कहा कि या तो आप इस संयुक्त संसदीय समिति की संस्तुति को वापस लेने की बात को हटा दें या मुझे इस दुनिया से हटा दें। इस पर सभी संसद सदस्यों ने संयुक्त संसदीय समिति की संस्तुति का साथ दिया। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने बहस को स्थगित कर दिया और आश्वासन दिया कि बहस उसी सत्र के अंत में की जाएगी। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा न हो सका क्योंकि 27 दिसंबर 1970 को लोकसभा भंग हो गई। इसी के साथ जनजातीय समाज के उत्थान और कल्याण का और उन पर हो रहे भीषण अन्याय को दूर करने का अवसर भी चला गया। यदि वह संस्तुति मंजूर हो जाती और संविधान में जनजातियों की परिभाषा में ईसाई एवं इस्लाम में धर्मांतरित लोगों की जनजातीय स्थिति निरस्त हो जाती तो अपनी संस्कृति और पहचान की रक्षा करने वाला स्वाभिमानी और देशभक्त जनजातीय समाज इस अन्याय से बच जाता। आज पांच दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यह अन्याय लगातार जारी है। बाबा कार्तिक उरांव आज नहीं है, लेकिन उनका दर्द अर्थात पूरे जनजातीय समाज का दर्द वैसे का वैसा बना हुआ है। ■

जनजातीय समाज से जुड़े मुद्दों पर अभाविप की बैठक

देश के जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने उत्तर प्रदेश स्थित ग्रेटर नोएडा में अखिल भारतीय जनजातीय छात्र कार्य बैठक का आयोजन किया। दो दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय जनजाति छात्र कार्य प्रमुख प्रमोद राउत, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य डा. आशुतोष मांडवी, उड़ीसा प्रांत छात्रा प्रमुख कविता कैंहर भी उपस्थित रहीं।

उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा कि भारत का सम्पूर्ण समाज सदियों से एक था। राजा भोज से लेकर राजा दाहिर तक देश भारतीय सनातन संस्कृति के आधार पर चलता था। धर्म आधारित न्याय व्यवस्था और सामाजिक समरसता के कारण एक जाति से दूसरा जाति में विवाह का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। देश में कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन अंग्रेजी सत्ता के काल खंड के दौरान भारतीय समाज में भेदभाव की स्थितियां बनाई गई। विशेषकर जनजातीय समाज को सनातन संस्कृति से अलग करने और जनजाति समाज की छवि को नष्ट करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सत्ता के कालखंड में भारतीय समाज को षड़यंत्र करके हिन्दू समाज को आर्य-द्रविण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग बांटने का काम किया। अंग्रेजी सत्ता के षड्यंत्रों को समझने की प्रबल आवश्यकता है क्योंकि भारतीय संस्कृति में सभी लोग लोग एक है और भेदभाव का कोई स्थान नहीं भारतीय संस्कृति में नहीं है।

दो दिवसीय बैठक के विभिन्न सत्रों के दौरान राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री गोविंद नायक, पूर्व राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डा. आशा लकड़ा, अखिल भारतीय जनजाति छात्र कार्य प्रमुख प्रमोद राउत, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य डा. आशुतोष मंडावी ने जनजातीय छात्रों का मार्गदर्शन किया। जनजाति क्षेत्र में उत्पन्न हुए विमर्श के विषय में चर्चा करते हुए पूर्व राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने कहा कि देश का जनजातीय समाज वीर, शक्ति संपन्न एवं स्वावलंबी था। रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, भगवान बिरसा मुंडा, वीर सुरेन्द्र साईं, टांटिया भील जैसे जनजातीय वीरों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। दुर्भाग्य यह है कि इतिहास में इन वीरों को सम्मानजनक स्थान नहीं मिला।

बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गोविंद नायक ने जनजातीय क्षेत्रों में संगठन कार्य विस्तार और सुदृढ़ीकरण के विषय में अपने विचार रखें। बैठक के दौरान जनजातीय छात्रों को शिक्षा, कैरियर, सुविधा सहित कई अन्य उपयोगी विषयों की जानकारी दी गई। साथ ही छात्रों से नए छात्रों को जोड़ने, छात्रावास में नियमित प्रवास करने, जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक नेतृत्व खड़ा करने के साथ ही तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा क्षेत्र में जनजातीय छात्रों की सहभागिता बढ़ाने पर चर्चा की गई। दो दिवसीय बैठक का आयोजन गत 11 एवं 12 सितंबर को किया गया। बैठक में आयोजित दस सत्रों में 25 प्रांतों के 91 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

भारतीय एवं पारंपरिक खेलों से होगा राष्ट्र भावना का निर्माण

खेलो भारत की दो दिवसीय कार्यशाला में आगामी योजनाओं पर हुई चर्चा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की गतिविधि खेलो भारत की दो दिवसीय अखिल भारतीय कार्यशाला में पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ भारतीय खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कार्यशाला में देश भर के 123 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

ग्वालियर स्थित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान गत 1 एवं 2 अक्टूबर 2024 को आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा कि सस्ती सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ खेल भी आवश्यक होता है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों का चौमुखी विकास होता है। खेलो भारत गतिविधि का मुख्य उद्देश्य आनंद में सार्थक जीवन भी है। अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा ने कहा कि जिस प्रकार अभाविप छात्रों को शूरवीर बनाती है, उसी तरह खेलो भारत गतिविधि पदकवीर बनाती है।

कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में चर्चा के दौरान अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री एस. बालकृष्ण ने प्रतिभागियों से भारतीय खेलों के आयोजन और उनमें हिस्सा लेने के लिए छात्रों को प्रेरित करने का आह्वान किया। कार्यशाला में भारत के परंपरागत खेलों के साथ ही वैश्विक स्तर के खेलों में भारत की सहभागिता और पदक तालिका में देश का स्थान बढ़ाने के संबंध पर गंभीर चर्चा हुई। कार्यशाला में खेलो भारत की राष्ट्रीय संयोजिका पल्लवी गारी ने खेलो भारत के उद्देश्य, खेलो भारत के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने और खेल के माध्यम से छात्रों में राष्ट्र भावना का निर्माण करने का आह्वान किया।

कार्यशाला के दौरान अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री एस. बालकृष्ण, खेलो भारत गतिविधि के

अखिल भारतीय प्रमुख प्रदीप शेखावत एवं खेलो भारत के राष्ट्रीय सह-संयोजक आशुतोष ने संगठनात्मक ढांचा, संरचना एवं परिसर में खेलो भारत की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में कार्य पद्धति, खेल संस्कृति के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों का प्रतिपादन, परिसर भ्रमण, खेलों के मिलने वाली आर्थिक सहायता, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले धन एवं खेल प्रतिभा खोज के साथ ही खेलो भारत की संगठनात्मक रचना, वर्तमान स्थिति, कार्यपद्धति और खेल संस्कृति में भारतीय जीवन मूल्यों का प्रतिपादन सहित आगामी योजनाओं पर विचार किया गया। कार्यशाला के समापन सत्र में खेलो भारत गतिविधि प्रमुख प्रदीप शेखावत ने कहा कि खेलो भारत के माध्यम से सभी प्रकार के खेलों के माध्यम से भारतीय एवं पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने का कार्य प्राथमिकता में शामिल है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

चुनौतियों के बाद भी दिखती हैं असीम संभावनाएं

■ अश्वनी शर्मा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता! दुनिया में इसको लेकर कहीं सकारात्मक तो कहीं नकारात्मक बहस जारी है। इसके उपयोग और प्रयोग को लेकर समूचा विश्व आशान्वित भी है और चिंतित भी। आने वाला समय संभावनाओं और विवादों से भरा हुआ है। कुछ महीने पूर्व केंद्र सरकार ने गूगल के एआई टूल जैमिनी पर प्रश्न खड़े किए हैं। जैमिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फांसीवादी बताया तो दूसरी ओर यूक्रेन के वर्तमान एवं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रप्रमुख के विषय में अलग प्रतिक्रिया मिली, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा आईटी अधिनियमों का उदाहरण देकर आपत्ति व्यक्त की गई। एआई टूल जैमिनी को दिसम्बर 2023 में गूगल के चैट जीपीटी की तुलना में अधिक कारगर बताकर शुरू किया गया था, जिसके टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन फीचर सहित अनेकों बदलाव की घोषणा भी की जा चुकी है।

एडवांस एआई की दुनिया का यह कोई पहला विवाद और बदलाव नहीं है। एक लंबी सूची इससे जुड़ी हुई है। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने के आरोप भी इससे जुड़े हुए हैं, वही डीपफ़ेक यानी छेड़छाड़ जैसे अनेकों विषय का परिणाम अभी आना बाक़ी है। एआई को लेकर दुनिया भर में उत्साह का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि दस लाख प्रयोगकर्ता का आंकड़ा छूने में नेटफिलिक्स को 41 माह, फेसबुक को 10 माह, इंस्टाग्राम को 2.5 माह लगे तो चैट जीपीटी को केवल पांच दिन। अमेजन के संस्थापक एवं पूर्व सीईओ जेफ़ बेजोस कहते है कि आगामी बीस वर्षों में एआई समाज पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, यह कहना कठिन है। लेकिन वह सरकारी संगठन एवं व्यवसाय को एआई के माध्यम से सशक्त बनाने की संभावनाओं को लेकर बेहद आशान्वित दिखते हैं। बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल इंक के सीईओ टिम कुक एआई को मानव को आगे ले जाने की संभावना के रूप में देखते हैं। वह एआई को मानव को बढ़ाने के रूप में देखते हैं, न कि मानव की जगह लेने के रूप में।

हाल ही में पहले ट्विटर और अब एक्स के नाम से जाने जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्म के मालिक एलन मस्क के एआई को लेकर विचार कुछ अलग है। वह इसे एक राक्षस की संज्ञा देते हैं और उसे नियंत्रित करने के वचन को विफल करार देते हुए दुनिया को इससे सावधान रहने के लिए आगाह भी करते हैं। भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि एआई ख़ुद को उस स्तर तक सुधार कर सकता है, जहां मानव द्वारा उस पर नियंत्रण कर पाना असंभव होगा। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं इंफोसिस के संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ति एआई से मानव जीवन की आसान राह देखते हैं। वह कहते हैं कि तकनीक कभी भी इंसानी दिमाग़ की जगह नहीं ले सकती। इंसान कभी ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि उनके पास मस्तिष्क की शक्ति है और बच्चे के मस्तिष्क की बराबरी कंप्यूटर कभी नहीं कर सकता। विज्ञान प्रौद्योगिकी की इन दिग्गज कंपनियों के निर्माताओं के विचारों की तरह ही दुनिया भर में एआई को लेकर बहस जारी है।

संभावनाओं की बात करे तो बहुत कुछ दिखाई देता है। काशी में आयोजित काशी-तमिल संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील, अनेक संभावनाओं से घिरी तकनीकी के अलग स्वरूप

का दर्शन कराती है। प्रधानमंत्री सभा में उपस्थित तमिल बंधुओं से हेडफ़ोन उपयोग करने की अपील करते हैं जिससे भाषिणी एप द्वारा उनका हिन्दी में दिया गया भाषण तमिल में सुना जा सके। इसी तरह जी-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री समूह की बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा इस अनुवाद मंच का उपयोग वैश्विक नेताओं के सामने किया गया।

मानव जीवन के लिए सहयोगी और वरदान साबित होने तक एआई का उपयोग ठीक है। परंतु इसके उपयोग की सीमा निर्धारित करने की अत्यंत आवश्यकता होगी क्योंकि सीमा से बाहर इसका उपयोग होने पर परमाणु शक्ति की कोडिंग और युद्ध में इसका उपयोग होने की स्थिति में, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता, इसके परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। साथ ही मानव को इसका मूल्य अपनी नौकरी देकर भी चुकाना पड़ेगा और इसके रुझान विश्वभर में देखे जा रहे हैं। ड्रापबॉक्स ने एआई के काम का हवाला देकर 60 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी करके इसकी शुरुआत कर दी है। एक्स ने भी अपने कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी की है। फादर ऑफ एआई कहे जाने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक हिंटन, जिन्होंने गूगल में एक दशक से अधिक अपनी सेवा दी, वह एआई को अपनी ऐतिहासिक भूल कहते है क्योंकि इसमें विकसित की जा रही बुद्धिमत्ता इंसानी बुद्धि से कही अधिक है।

विश्व की पहली एआई रोबोट साफिया कुछ वर्ष पहले भारत आई थी। संपूर्ण विज्ञान क्षेत्र इस उपलब्धि पर उत्साहित भी है और आश्चर्यचकित भी। गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी में बने फूडकोर्ट में मानव के स्थान पर कर्मचारी के रूप में अब रोबोट भी काम करने लगे हैं। हर क्षेत्र में इसके उपयोग की संभावनाओं को देखा जा रहा है। अयोध्या में भव्य श्रीरामजन्ममंदिर के प्राणप्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान प्रभु श्रीराम के एआई निर्मित विभिन्न चित्रों की सभी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर देखा। एआई आने के बाद संपर्क और संवाद के माध्यमों में भी बढ़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्चुअल असिस्टेंट या आभासी सहायक अब स्थानीय भाषाओं में भी अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है।

फिलहाल समय के गर्भ में बहुत कुछ छिपा है और भविष्य को जानने के लिए भूतकाल का अध्ययन आवश्यक है। भारतीय ऋषि-मुनियों, पूर्वजों द्वारा लिखित ग्रंथों में इसके संदर्भ को खोजना भी आवश्यक है। भारत सदियों से संपूर्ण विश्व के लिए शोध का विषय रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा पर जोर दिया गया है। भारतीय संस्कृति के पितामह ऋषि-मुनियों, जो कि शोधकर्ता थे, उन्होंने हर क्षेत्र में नवाचार किए। इसके अनेकों उदाहरण हैं। परमाणु अवधारणा के जनक आचार्य कणाद, नक्षत्रों के खोजकर्ता गर्गमुनि, योगशास्त्र में रचयिता पंतजलि एवं चरक संहिता की रचना करने वाले आचार्य चरक-यह सभी वह शोधकर्ता थे, जिनके सूत्र एवं शोध आज भी केवल प्रासंगिक ही नहीं हैं, अपितु विश्वभर के लिए खोज का विषय बने हुए हैं।

वेदों में वर्णित चेतना की अवधारणा एआई के लिए महत्वपूर्ण आधार है। वेदों के दार्शनिक और व्यावहारिक ज्ञान को एआई सिस्टम पर लागू किया जा सकता है। चेतना, मशीन लर्निंग, ध्वनि कंपन, कर्म और नैतिकता की अवधारणाएं, जो सभी वेदों में हैं, एआई की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं और उसे एक ऐसा मूल्यवान उपकरण बना सकती हैं जो मानव जीवन को और बेहतर कर सकता है। वैदिक अवधारणाओं को एआई में समाहित करने से नैतिक, दयालु और टिकाऊ प्रौद्योगिकी प्राप्त हो सकती है। इसीलिए एआई क्षेत्र के लिए भारत के वेदों का महत्व बहुत अधिक है और उनके एकीकरण से अभूतपूर्व विकास हो सकता है। मानवता के लिए इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। एआई से जुड़े उपयोग के डर के बीच यह सुनिश्चित है कि भारत ही दुनिया को इससे संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण आधारित विकास और मानव सहायक तंत्र की गारंटी देगा, जिससे श्रीमदभागवतगीता में वर्णित चेतना शक्ति का विश्वहित में उपयोग करके जगत को श्रेष्ठ बनाने की वेद प्रदत्त आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन संभव हो सकेगा। ■

J&K Assembly Elections The Aftermath

■ **K. N. Pandita**

NC, Congress, and CPM (42+6+1 = 49) will form new government in Srinagar. On the national level, they are part of the INDIA alliance's agenda of ousting Narendra Modi. On the regional level, their prioritized agenda, according to the NC manifesto, is (a) restoration of statehood, (b) abrogation of the State Reorganization Act, (c) restoration of special status, including the two articles of the Indian Constitution, (d) development, and (e) employment for the unemployed youth.

Long back the Home Minister had said that the statehood would be restored at its proper time. New Delhi remains committed. Hence it is no issue but of course, the proper time will be decided by the Home Ministry.

The power of restoration of Articles 37 and 35-A rests with the parliament. The present parliament will not do anything like that. How is the NC-led coalition going to face it? Omar says we cannot do anything about it as long as the NDA is in power. Nobody can predict events shaping post-2029.

The question is how the NC-led government will face the people. Dr Farooq has crossed all boundaries of propriety in denigrating Modi. He cannot face him. So he is using his son as an alibi, and it is through him that he schemed to convey to the Centre that the new government would like reconciliation knowing well that Article 370 is not going away in any way because there is the judgement of the Supreme Court of India.

As regards development and youth employment, it all depends on resources. J&K is incapable of raising funds to meet these requirements. The problem facing it is that the days are gone when NC blackmailed the Congress government and squeezed huge funds but refused to submit the account of expenditure for billions of rupees. The present government will not succumb to blackmail. Thus state-centre relations have to be restructured along new and unprecedented norms with which neither the state political leadership, nor the bureaucratic chapter is happy.

Another challenge before the new government is that it hasn't won a single seat from Doda, Kishtwar, Jammu, Samba, Reasi, Udhampur and Kathua constituencies all falling in Jammu Division. It means these important areas will not have representation in the government. Majority vote is not the only criterion in a heterogeneous democracy; representative character of the government is a compulsion.

BJP representative in J&K, Ram Madhav clarified in a press interview that though coalition no doubt is an option in a democratic process but his party has not concentrated on the idea. Maybe his experience with a coalition with the PDP in the past could serve as a guiding factor.

The nature of relationship between NC and Congress in coalition is also an issue. We can elaborate this aspect only when the formal structure of the Council of Ministers is known. How the prospective incumbents will react to it is to be ascertained. It is no surprise that Rahul Gandhi has taken serious objection to NC not consulting his party about who would be the Chief minister. The Congress has been punished in Jammu just because, despite the party's infamy and scandalous role, the traditional Congresses in Jammu had tried to play a holier-than-thou role in castigating BJP.

One very important outcome from this analysis relates to the future of the Jammu region. If the valley-centric new government remains irreconcilable on Article 370 issue by putting forth the argument that revocation of the State

Reorganization Act of 2019 is its commitment to the people of the valley, then the demand of Jammu for a separate entity gets immensely strengthened because of regional polarization. What options are before the new government other than those of abandoning the dominance of the valley over Jammu and sharing power with the opposition by devising a mechanism that would respond to the twin demand of power-sharing and ultimate recognition of Jammu as an equal and at-par entity?

Omar does understand this complex situation and has also mildly hinted at it but any reconciliation and re-adjustment is gall to Farooq and his rabid anti-New Delhi coterie. Moreover, Farooq is committed to the INDIA alliance in supporting the ouster of Modi, who, as the situation indicates, will neither bend to their demands nor quit office until the full term ending in 2029. Farooq has to understand that there is no option left for him other than behaving as a federating unit of the Indian Union. His rhetoric of talks with Pakistan makes is meaningless.

Another ticklish issue that is going to lend strength to a spectre of confrontation with the Centre is the powers conferred upon the LG of nominating five members to the assembly. Omar Abdullah has made a couple of statements arguing that the powers of nominating five members for the assembly should rest with the assembly and not the LG as that would be a denial of democratic dispensation. Will the new government rush to the Supreme Court for its intervention in the administrative arena, is anybody's guess.

In short, the new government in Srinagar is now at the crossroads of history. Will it choose the path of sanity, collaboration and reconciliation in the interests of the people of J&K or will it continue along the path of confrontation and clash and thus set in another decade or two of political inactivity and paralysis for the State? Should the new government choose the path of reconciliation and cooperation, the first and foremost step in that direction would be a clear time table for the return and rehabilitation of the displaced people especially the Kashmiri Pandits back in the valley strictly according to their convenience. This announcement will give great stability and public support of the Indian nation to the new government in J&K. The new government cannot escape shouldering this responsibility. ■

I राजस्थान I

अभाविप ने किया प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के 664 प्रतिभाशाली छात्रों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप)-चित्तौड़गढ़ द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। प्रतिभाशाली छात्रों का चयन शिक्षा, खेल, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) सहित अन्य क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर किया गया। अभाविप-चित्तौड़गढ़ के जिला संयोजक विपुल सिंह राणावत ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में चित्तौड़गढ़ जिले के जिलाधिकारी आलोक रंजन और मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अश्वनी शर्मा ने हिस्सा लिया। समारोह में चित्तौड़ प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री वीरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ विभाग प्रचारक सत्यनारायण, प्रांत कार्यकारिणी संगीता चौहान सहित बड़ी संख्या में अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अपने संबोधन में जिलाधिकारी आलोक रंजन ने सभी छात्रों से स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। मुख्य वक्ता अश्विनी शर्मा ने अभाविप के आंदोलन, प्रदर्शन, गतिविधि,आयाम कार्यों से विद्यार्थियों को अवगत कराया और राष्ट्र हित में कार्य करने का आह्वान किया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

अभाविप ने लहराया जीत का परचम

असम, पंजाब एवं उत्तराखंड के विभिन्न महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के चुनावों में अभाविप को मिली बढ़त

देश के कई महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में संपन्न छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) को ऐतिहासिक जीत मिली है। असम, उत्तराखंड में उल्लेखनीय विजय हासिल करने के साथ ही अभाविप ने पंजाब विश्वविद्यालय में ग्यारह वर्ष बाद पुनः अपनी वापसी की है।

असम में अभाविप की ऐतिहासिक जीत

पूर्वोत्तर भारत के प्रतिष्ठित गुवाहाटी विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव में अभाविप ने पहली बार अध्यक्ष पद जीत कर इतिहास रच दिया है। गत 26 सितंबर को हुए गुवाहाटी विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर अभाविप प्रत्याशी मानस प्रतीम कलिता ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया (एनएसयूआई) के प्रत्याशी अंकुर ज्योति भराली को 573 मतों से हराया। चुनाव में पड़े 2483 मतों में से अभाविप के निर्वाचित अध्यक्ष मानस प्रतीम कलिता को 1258 मत प्राप्त हुए, जबकि एनएसयूआई एवं आसू प्रत्याशी को क्रमशः 685 और 447 मत मिले। कथित रूप से आसू एवं एनएसयूआई का गढ़ माने जाने वाले गुवाहाटी विश्वविद्यालय में छात्रों ने चंदाजीवी आसू एवं गुंडागर्दी का प्रतीक बन चुकी एनएसयूआई को सबक सिखाते हुए अभाविप को चुना।

इसी तरह डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में व्यायामशाला सचिव पद पर अभाविप प्रत्याशी पलाश रंजन एवं सामान्य खेल सचिव पद पर अनुराग सैकिया ने जीत हासिल की। यहां के छात्रों ने भी आसू और एनएसयूआई को पूरी तरह से नकार दिया। तेजपुर विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव में भी अभाविप के प्रांत केंद्रीय विश्वविद्यालय संयोजक प्रज्ञानदीप बोरा ने महासचिव पद पर बड़ी जीत दर्ज की। वहीं केंद्रीय संस्थान राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में हुए छात्रसंघ चुनाव में अभाविप के प्रांत सह-मंत्री सरंगा कौशिक फूकन ने महासचिव के पद पर अपना परचम लहराया। होजाई स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में अभाविप ने अध्यक्ष, महामंत्री जैसे प्रमुख पदों पर निर्विरोध जीत हासिल की। यहां बारह में से दस पदों पर अभाविप को जीत मिली है। बी. बरुआ महाविद्यालय, दररंग महाविद्यालय, गुवाहाटी कालेज, गुवाहाटी कॉमर्स कालेज, नलबाड़ी कॉमर्स कालेज, भोलानाथ कालेज (धुबरी), लखीमपुर कॉमर्स कालेज, धेमाजी कालेज, सिलचर गर्ल्स कालेज, लंका महाविद्यालय, मंगलदोई कॉमर्स कालेज, स्वामी विवेकानंद कालेज जैसे अधिकांश संस्थानों में अभाविप ने अपने जीत दर्ज कराई है। अभाविप के प्रदेश मंत्री हेरोल्ड मोहन ने कहा कि असम में हुए छात्र संघ चुनाव के परिणामों ने यह दिखा दिया है कि मां कामाख्या को अपना आराध्य देव मानते हुए छात्र राष्ट्रवाद के साथ हैं एवं लाचित बरफुकन के विचारों से प्रेरित है।

उत्तराखंड में भी आगे रही अभाविप

उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में संपन्न छात्रसंघ चुनाव में भी अभाविप ने जीत का परचम लहराया है। विश्वविद्यालय के तीनों परिसर क्रमशः बिड़ला परिसर, बीजीआर परिसर एवं एसआरटी परिसर में अभाविप ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर (श्रीनगर) में अभाविप

के जसवंत राणा अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में आशीष पंत विजयी हुए। वहीं विश्वविद्यालय के टिहरी परिसर में सभी पदों पर अभाविप ने निर्विरोध जीत हासिल की, जबकि पौड़ी परिसर में अध्यक्ष पद पर अभाविप प्रत्याशी अभिरुचि विजय हुई हैं। छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर अभाविप के जसवंत सिंह राणा को 1861 और विरेंद्र सिंह को 1403 मत मिले। इसी तरह निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ चंद्र सानू को 147 मत हासिल हुए। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (यूआर) पद पर अभाविप के आशीष पंत को 2090 मत मिले और उन्होंने 837 मतों से जीत अपने नाम की। अबकी बार सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर नामांकन रद्द होने के कारण चुनाव नहीं हुआ। चुनाव में 3454 छात्र-छात्राओं ने अपने मत का प्रयोग किया।

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर (पौड़ी) में संपन्न छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अभिरुचि नौटियाल 275 मत पाकर अध्यक्ष चुनी गई। उन्होंने एनएसयूआइ के प्रत्याशी राजकुमार को पराजित किया। एसआरटी परिसर (टिहरी) में अभाविप के प्रत्याशी निर्विरोध जीते। 1973 में स्थापना के बाद से यहां पहली बार छात्र संघ के समस्त पदाधिकारियों की कार्यकारिणी सभी पदों पर एकल नामांकन होने के कारण निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अध्यक्ष पद पर आदित्य रतूड़ी, उपाध्यक्ष पद पर विपिन सिंह नेगी, सचिव पद पर अमन सजवान, सह सचिव पद पर धीरज चंद्र पाल, कोषाध्यक्ष पद पर मृदुल मखलोगा, कार्यकारिणी सदस्यों में स्नेहा पुंडीर, सलिल प्रताप सिंह, शाहिद और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि उज्जवल उनियाल को चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।

पंजाब विश्वविद्यालय में ग्यारह वर्ष बाद लहराया भगवा

पंजाब विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में ग्यारह वर्ष बाद अभाविप ने संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज कर अपनी वापसी की है। छात्रसंघ चुनाव में अभाविप एक मात्र ऐसा संगठन रहा, जिसने बिना किसी गठबंधन के चुनाव में हिस्सा लेकर जीत हासिल की। अभाविप ने विश्वविद्यालय के चार पदों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें शेष तीन पदों पर अभाविप प्रत्याशी मामूली अंदर से भले ही जीत से पीछे रहे गए, लेकिन छात्रों के दिल जीतने में सफल रहे। पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल के चुनाव में अभाविप ने अध्यक्ष पद पर अर्पिता मलिक, उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक कपूर, महासचिव पद पर शिवनंदन रिक्की एवं संयुक्त सचिव पद पर जसविंदर राणा को प्रत्याशी बनाया था। पंजाब विश्वविद्यालय में जीत हासिल करने के बाद अभाविप ने कहा कि यह जीत सिर्फ अभाविप की नहीं है, बल्कि हर उस छात्र की है, जिसने अभाविप के विजन में विश्वास करने के साथ सकारात्मक बदलाव के लिए अभाविप पर भरोसा किया। नवनिर्वाचित संयुक्त सचिव जसविंदर राणा ने अभाविप टीम की प्रतिबद्धता को सामने रखते हुए कहा कि अभाविप को मिले समर्थन से वह अभिभूत हैं। अभाविप की जीत छात्रों की एक स्पष्ट जनादेश है, जो यह दर्शाता है कि वह एक सफल और सशक्त नेतृत्व चाहते हैं। अभाविप अपने वादों को पूरा करने और पंजाब विश्वविद्यालय में हर छात्र की आवाज बनने के लिए पूरी मेहनत करेगी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

ABVP Shillong Organised Prestigious U. Tirot Sing Best Students Awards

The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) Shillong organised the prestigious "U Tirot Sing" Best Student Award 2024 at the U Soso Tham Auditorium, Shillong. The event witnessed the participation of over 1000 students, parents, and well-wishers from various schools across the city.

The program was graced by the presence of distinguished guests. Shri Pabitra Margherita, Union Minister of State for External Affairs and Textiles attended as the Chief Guest. Dr. Kestonbel Manik Syiemlieh, the 5th descendant of U Tirot Sing Syiemlieh, was also present as a special guest, while Dr. C. A. Sashan Khongthohrem, the State President of ABVP Meghalaya, was a notable guest for the event.

The highlight of the program was the felicitation of over 150 school toppers from the 2024 SSLC and HSSLC examinations. These students, representing various institutions across Shillong, were recognized for their outstanding academic achievements, symbolizing the spirit of excellence and hard work that U Tirot Sing exemplified.

On the 12th of September, 2024, the event not only celebrated the academic achievements of the students but also honored the legacy of U Tirot Sing Syiemlieh, a revered freedom fighter from Meghalaya, whose values of bravery, leadership, and service continue to inspire generations. The atmosphere was one of pride and motivation, as students, parents, and teachers alike were reminded of the importance of dedication and perseverance in education. The "U Tirot Sing" Best Student Award continues to be a beacon of encouragement for the youth of Meghalaya, promoting academic excellence and leadership among students. ■

(Rashtriya Chhatrashakti Team)

ABVP Delegation Met Union Health Minister

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) Jammu & Kashmir has raised critical concerns regarding the challenges faced by B.Sc Nursing aspirants under the Prime Minister's Special Scholarship Scheme (PMSSS).

In a memorandum submitted to the Union Health Minister J. P. Nadda, ABVP outlined several issues stemming from recent amendments by the Indian Nursing Council, which made it mandatory for students to qualify either the NEET or JKCET for admission to nursing colleges. The timing of these examinations has created significant overlap with the PMSSS registration period, leaving many students unable to register for the necessary entrance exams.

Akshi Billowria, ABVP State Secretary, said that newly brought amendment by Indian Nursing Council dated 10th April 2024, that for getting admission in B.Sc nursing colleges NEET or JKCET has been made mandatory. The registration process for NEET was started from 9th Feb-10th April & JKBOPEE registration from 05 May-26 May and PMSSS scheme portal for registration was available from 18 June to 29 July. As a result of which students were not able to register in either JKBOPEE or NEET examination and are now rendered ineligible for admission in BSC Nursing.

ABVP have urged the Health Minister to clarify these criterias and support the affected students, advocating for a review of the policies to ensure equitable access to education for all aspiring nursing professionals in Jammu Kashmir. The organization remains committed in representing the interests of the students and facilitating dialogue with authorities to address these pressing issues.

ABVP demands from authorities to address the concerned issue that one time exemption to qualify NEET or JKCET for admission in B.Sc nursing under PMSSS shall be provided. So that those students who were not able to register in either of said examination be made eligible for seeking admission in respective courses. The delegation included State Secretary Akshi Billowria,Tilak Thakur, Harish Sharma, Deepali Goswami. ■

(Rashtriya Chhatrashakti Team)

अभाविप राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रतीक चिह्न का अनावरण

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए अभाविप के प्रतीक चिह्न (लोगो) का अनावरण गोरखपुर विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। प्रतीक चिह्न का अनावरण अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. राजशरण शाही, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, छात्रा कार्य प्रमुख प्रो. मनु शर्मा कटारिया, केंद्रीय कार्यालय मंत्री दिगंबर पवार एवं केंद्रीय सह कार्यालय मंत्री सौरभ पाण्डेय ने किया।

जानकारी हो कि अभाविप का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 22 नवंबर से 24 नवंबर के मध्य गोरखपुर में आयोजित होने जा रहा है। देश के साथ ही कई अन्य देशों के प्रतिनिधि भी अधिवेशन में हिस्सा लेगें। अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. राजशरण शाही ने बताया कि नाथ सम्प्रदाय की पावन भूमि गोरखपुर में विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अभाविप का होने वाला 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन धार्मिक तथा शैक्षिक दोनों रूपों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के विभिन्न प्रांतों तथा विदेशों से आने वाले प्रतिनिधि अपने-अपने प्रांतों की संस्कृति एवं पारंपरिक परिधानों में अनेकता में एकता की भव्यता एवं सुंदरता का परिचय देते हुए एक सम्पूर्ण लघु भारत का विराट रूप प्रस्तुत करेंगे। साथ ही अधिवेशन में आगामी कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

प्रा. रविंद्र केसरी शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन

अभाविप बिहार प्रांत के प्रथम संगठन मंत्री थे प्रा. रविंद्र केसरी

शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) बिहार प्रांत के प्रथम संगठन मंत्री प्रा. रविंद्र केसरी शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सैंकड़ों शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं हेतु सम्मानित किया गया। समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल सहित बड़ी संख्या में अभाविप कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

विद्यार्थी विकास परिषद (पटना महानगर) के तत्वावधान में ए. एन. कालेज के सभागार में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि छात्र शक्ति से ही राष्ट्र शक्ति होती है। समाज में शिक्षकों के योगदान को कोई भी नकार नहीं सकता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने छात्रों में अधिक से अधिक गुणवत्ता के बीज रोपित करें और छात्रों का यह दायित्व है कि वह अपने शिक्षकों के माध्यम से अधिक से अधिक गुणों को विकसित करें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राय ने भारतीय समाज को जोड़ने में अभाविप के योगदान का उल्लेख करते हुए छात्रों से राष्ट्रवादी छात्र संगठन अभाविप से जुड़ने और देश को पुनः विभाजित करने की मंशा रखने वाले छद्म भेषियों से सतर्क रहने की अपील भी की।

समारोह में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने प्रा. केसरी को कर्मठ एवं कुशल प्रशासक बताते हुए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि जिस समय बिहार में अभाविप के गिने-चुने कार्यकर्ता होते थे, उस विषम परिस्थितियों में भी प्रा. केसरी ने कठिन परिश्रम और लगन से अभविप संगठन को खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका संपूर्ण जीवन बिहार एवं संगठन के लिए समर्पित रहा है।

समारोह में अभाविप के प्रान्त संगठन मंत्री रोशन सिंह, विभाग संयोजक रोशन शर्मा, महानगर अध्यक्ष डा मुकेश झा, महानगर संगठन मंत्री प्रशांत गौतम, महानगर मंत्री प्रियरंजन सिंह सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन महानगर उपाध्यक्ष डा. बैकुंठ रॉय ने किया। समारोह का आरंभ प्रा. केसरी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया।

जानकारी हो कि स्वर्गीय प्रोफेसर रविंद्र केसरी का जन्म मुंगेर जिले में हुआ था। वनस्पति विज्ञान में पीएचडी करने के बाद 1959 में वह पटना साइंस कालेज के प्रोफेसर बने। 1972 में उन्होंने अभाविप बिहार प्रदेश के प्रथम संगठन मंत्री का दायित्व संभाला और प्रदेश में अभाविप संगठन को खड़ा करने में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

सुधी पाठकों!

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' अक्टूबर 2024 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

सोरेन सरकार की विफलताओं पर अभाविप ने जारी किया काला दस्तावेज

झारखंड सरकार की विफलताओं पर केंद्रित काला दस्तावेज जारी करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दस्तावेज में अभाविप ने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार एवं महिला सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार की असफल नीतियों एवं कार्यक्रमों का खुलासा किया है। साथ ही राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों की विस्तृत जानकारी देते हुए सरकार के दावों की पोल खोल दी है।

रांची विश्वविद्यालय स्थित दीक्षांत मंडप में गत 15 सितंबर को आयोजित छात्र गर्जना कार्यक्रम में अभाविप ने काला दस्तावेज जारी किया। राज्य सरकार द्वारा किए गए कथित विकास पर व्यंग्य करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवारजनों का ही विकास हुआ और विकास के नाम पर आदिवासी छात्र, युवा, किसान, मजदूर के साथ छल किया गया। अभाविप की यह लड़ाई झारखंड की अस्मिता बचाने, बहन-बेटियों के सम्मान को बनाए रखने एवं युवाओं को रोजगार देने की है। इस लड़ाई में अभाविप का प्रत्येक कार्यकर्ता सहभागी बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक हिस्से में जाकर अभाविप के कार्यकर्ता विधायक, मंत्री और कार्यकर्ताओं से विकास सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर मांगेंगे।

छात्र गर्जना कार्यक्रम में प्रदेश सह मंत्री शुभम राय ने कहा कि सभी कार्यकर्ता घर-घर जाकर आम लोगों को प्रशासक को काला दस्तावेज देकर वर्तमान राज्य सरकार की खोखली नीति को समाज के बीच रखने का प्रयास करेंगे। प्रदेश मंत्री सौरभ झा ने कहा कि वर्तमान सरकार की नकारात्मक कार्य प्रक्रिया के कारण राज्य के संताल परगना की जनसंख्या में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। लव जेहाद, लैंड जेहाद की की आड़ में राज्य की अस्मिता और संस्कृति को खोखला किया जा रहा है।

छात्र गर्जना कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद एक्का, प्रदेश मंत्री सौरभ झा सहित प्रदेश के अन्य सह मंत्रियों ने हिस्सा लिया। काला दस्तावेज विमोचन में प्रांत प्रमुख डा. पंकज कुमार, अखिल भारतीय जनजातीय छात्र कार्य प्रमुख प्रमोद राउत, प्रदेश संगठन मंत्री नीलेश कटारे, प्रांत कार्यालय मंत्री शुभम पुरोहित, कार्यक्रम संयोजक विशाल सिंह सहित हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं भी उपस्थित रहीं। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

मिशन साहसी प्रशिक्षण शिविर में छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुर

महिला सुरक्षा से जुडी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने पहल की है। राज्य में छात्राओं को सशक्त एवं आत्मरक्षा के लिए उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए अभाविप ने मिशन साहसी का आयोजन प्रारंभ किया है। मिशन साहसी का उद्देश्य छात्राओं को निडर और शक्तिशाली बनाना है, जिससे वह विपरीत स्थितियों ने सफलतापूर्वक अपना बचाव कर सके।

'मिशन साहसी' अभियान के अंतर्गत अभाविप और विद्यार्थी विकास न्यास द्वारा कुशल प्रशिक्षक की निगरानी में राजधानी कोलकाता स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण परिसर में छात्राओं के लिए दो दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गत 14 एवं 15 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को कमांडो प्रशिक्षक शिफूजी शौर्य भारद्वाज के नेतृत्व वाली टीम ने आत्मरक्षा से जुडी विभिन्न तकनीक का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को विभिन्न परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा करने और शारीरिक-मानसिक रूप से स्वयं को तैयार करने से जुड़े बिंदुओं से अवगत कराया गया।

महिला सुरक्षा की बदतर स्थितियों के बीच राज्य में मिशन साहसी के आयोजन को एक गंभीर एवं सकारात्मक प्रयास बताते हुए अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कालेज में हुई वीभत्स घटना और संदेशखाली सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विरोध में पूरा देश उठ खड़ा हुआ है। राज्य में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के विरुद्ध युवाओं की देशव्यापी सशक्त आवाज बनने और छात्राओं तथा युवतियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत एवं सशक्त करने के लिए अभाविप ने मिशन साहसी जैसा महत्वपूर्ण रचनात्मक अभियान प्रारंभ किया है। मिशन साहसी का आयोजन राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण रचनात्मक हस्तक्षेप है। उन्होंने बताया कि

छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए अभाविप ने मिशन साहसी अभियान 2018 में आरंभ किया था। अभियान के तहत अब तक पूरे देश में आयोजित सैकड़ों आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पंद्रह लाख से अधिक छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मिशन साहसी अभियान को राज्य की छात्राओं को सशक्त बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम बताते हुए अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा ने कहा कि दो दिवसीय कार्यक्रम में जिन छात्राओं को प्रशिक्षण मिला है, वह महिलाओं की सशक्त आवाज बनकर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगी।

दो दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष रश्मि सामंत ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि मिशन साहसी जैसे रचनात्मक कार्यक्रम निश्चित ही राज्य की युवतियों तथा छात्राओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त और बेहतर करने का रास्ता दिखाएगा। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रूपा गांगुली और विशिष्ट अतिथि के रूप में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष रश्मि सामंत के साथ ही राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री गोविन्द नायक, राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा एवं शिफूजी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

विद्यार्थी पढ़ेंगे 'राष्ट्रीय युद्ध स्मारक' पर कविता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2023 के विजन के अनुरूप रची गई 'राष्ट्रीय युद्ध स्मारक' शीर्षक वाली कविता और 'वीर अब्दुल हमीद' शीर्षक वाले एक अध्याय को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के कक्षा छह के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की गई इस पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों में देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण तथा साहस और बलिदान के मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार 'राष्ट्रीय युद्ध स्मारक' कविता स्मारक के पीछे की भावना की सराहना करती है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना प्रत्येक नागरिक में उच्च नैतिक मूल्यों, बलिदान, राष्ट्रीयता की भावना और अपनापन जगाने तथा राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए की गई है। इसी तरह 'वीर अब्दुल हमीद' शीर्षक वाला अध्याय बहादुर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद के सम्मान में है, जिन्होंने 1965 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

वैश्विक स्तर पर राजनीतिक शक्तियों को प्रभावित कर रही हैं अमेरिकी कंपनियां : आईटीयूसी

अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ (आईटीयूसी) की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि अमेजन, टेस्ला, मेटा जैसी कंपनियां विश्व के अनेक देशों में राजनीतिक शक्तियों को प्रभावित कर रही है। यह कंपनियां एक तरफ जलवायु संकट को बढ़ावा दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रम अधिकारों का उल्लंघन भी कर रही हैं। आईटीयूसी द्वारा गत सितम्बर माह में जारी रिपोर्ट में अमेजन, टेस्ला, मेटा, एक्सॉनमोबिल, ब्लैकस्टोन, वैनगार्ड और ग्लेनकोर जैसी कंपनियों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सभी कंपनी कई महाद्वीपों पर यूनियन तोड़ने और कम वेतन, ई-कॉमर्स में एकाधिकार, अपने डाटा केंद्रों के माध्यम से अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन, कारपोरेट कर चोरी और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक ध्रुवीकरण में संलिप्त हैं। रिपोर्ट में सोशल मीडिया कंपनी मेटा की भूमिका पर भी कई गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कंपनियां लंबे समय तक चलने वाला खेल खेल रही हैं। यह हर स्तर पर लोकतंत्र से सत्ता को हटाकर ऐसे लोकतंत्र में ले जाने का खेल है, जहां उन्हें श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभावों की चिंता नहीं है। जानकारी हो कि आईटीयूसी में विश्व के 169 देशों और क्षेत्रों के श्रमिक समूह सहयोगी शामिल हैं। इनमें अमेरिका में श्रमिक संघों का सबसे बड़ा महासंघ एएफएल-सीआईओ और ब्रिटेन में ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस भी शामिल है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

एक देश-एक चुनाव

उच्च स्तरीय रिपोर्ट को मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति

एक देश-एक चुनाव के प्रस्ताव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत 18 सितंबर को अपनी स्वीकृति दे दी है। उच्च स्तरीय समिति का गठन 2 सितंबर 2023 में किया गया गया था। उच्च स्तरीय समिति ने सात देशों की चुनाव व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद 191 दिन में 18 हजार 626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट इसी वर्ष 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी। रिपोर्ट में सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया गया है। देश की 543 लोकसभा सीट एवं सभी राज्यों की 4130 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ चुनाव कराने की संस्तुति करने वाली रिपोर्ट विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित व्यापक तौर पर हितधारकों से विस्तृत परामर्श करके तैयार की गई है। एक देश-एक चुनाव की प्रक्रिया दो चरणों में लागू करने करने की अनुशंसा करने वाली रिपोर्ट में पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा और दूसरे चरण में आम चुनावों के सौ दिनों के अंदर स्थानीय निकाय के लिए निर्वाचन (पंचायत और नगर पालिका) करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही सभी निर्वाचनों के लिए एक समान मतदाता सूची तैयार करने और रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए देश में विस्तृत चर्चा आरम्भ करने एवं एक कार्यान्वयन समूह गठित करने की अनुशंसा की गई है। जानकारी हो कि देश में 1951 से 1967 के मध्य एक साथ निर्वाचन संपन्न हुए थे। विधि आयोग (1999) ने भी पांच वर्षों में एक लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक निर्वाचन कराने की अनुशंसा की थी, जबकि संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट (2015) में दो चरणों में एक साथ निर्वाचन कराने के तरीके सुझाए गए थे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। शतरंज ओलंपियाड ।

भारत ने लिखा नया इतिहास

हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण में भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने अपनी-अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल करके इतिहास लिख दिया है। गत 10 सितंबर से 23 सितंबर के मध्य आयोजित शतरंज ओलंपियाड में ऐसा पहली बार हुआ, जब भारत ने पुरुष एवं महिला दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किए। इससे पहले 2018 जॉर्जिया में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में चीन ने पुरुष एवं महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था।

बुडापेस्ट में आयोजित शतरंज ओलंपियाड की पुरुष टीम में अर्जुन एरिगासी, रमेशबाबू प्रगननंधा, डोम्माराजू गुकेश, विदित गुजराती और पेंटाला हरिकृष्णा की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष टीम को स्वर्ण पदक और हैमिल्टन रसेल कप से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम कुल 22 में से 21 पॉइंट्स हासिल करके अंक तालिका में शीर्ष पर रही, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे और उज्बेकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में 180 देशों ने हिस्सा लिया।

भारतीय महिला टीम में हरिका द्रोणावली, वैशाली रमेशबाबू, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेव और कप्तान अभिजीत कुंटे ने जीत में अहम भूमिका निभाई। भारतीय महिला टीम ने 11वें राउंड में अजरबैजान को हराकर स्वर्ण पदक और वेरा मेनचिक कप जीता। महिला टीम ने 22 अंकों में से 19 अंक हासिल किए ।

शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम ने गैप्रिंडाश्विली कप पर अपना कब्जा बरकरार रखा, जो पुरुष और महिला वर्गों में सर्वश्रेष्ठ संयुक्त परिणाम के लिए प्रदान किया जाता है। 2022 में तमिलनाडु में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम ने गैप्रिंडाश्विली कप हासिल किया था। रूस के बाद भारत दूसरा देश बन गया है, जिसने गैप्रिंडाश्विली कप को अपने पास बरकरार रखा है। जानकारी के अनुसार आगामी शतरंज ओलंपियाड उज्बेकिस्तान स्थित ताशकंद में 2026 में आयोजित किया जाएगा। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

पटना : शिक्षक सम्मान समारोह का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, अभाविप राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल एवं अन्य

ग्वालियर : खेलो भारत कार्यशाला को संबोधित करते अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री एस. बालकृष्ण, साथ में हैं खेलो भारत गतिविधि के अ. भा. प्रमुख प्रदीप शेखावत एवं अभाविप राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 OCTOBER, 2024
DATE OF PUBLISHING: 8 OCTOBER, 2024

POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI
POSTING REGISTRATION NO. DL(C)-11/1409/2024-26

मिशन साहसी

कोलकाताः मिशन साहसी प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करते हुए प्रशिक्षक शिफू जी शौर्य भारद्वाज, अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा, पूर्व राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास एवं अन्य

आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेती हुई छात्राएं